क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 02, गुरुवार, 24 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार-समाचार

अगर कर रहे हैं टैक्स चोरी तो 21 दिनों में करें रिटर्न फाइल, नहीं तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों की पहचान की है जो बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, टैक्स देने वाली इनकम है, लेकिन वे इनकम टैक्स नहीं भरते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) की मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसे लोगों की पहचान की है. ऐसे लोगों को विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे 21 दिनों के भीतर रिटर्न फाइल कर दें या फिर टैक्स असेसमेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी दे दें. जानकारी मिलने के बाद ऐसे मामलों की जांच की जाएगी. जो लोग इसकी जानकारी नहीं देते हैं, वे अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लंबे समय से ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो टैक्सेबल इनकम के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया. हालांकि, विभाग की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया कि ऐसे कितने लोग हैं.

मां-बाप के अलग होने पर PAN आवेदन में मां का नाम लिखना ही होगा काफीइनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबकुछ ऑनलाइन कर दिया है. यदि आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है कि आप पर कितना टैक्स बनता है और इसे किस तरह भरा जाए. पहले की तरह अब रिटर्न फाइल करने के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.

बेरोजगारी पर उलझी मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, 15 महीने में 73 लाख लोगों को मिली नौकरी

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है. विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है. तमाम राजनीतिक और आर्थिक एक्सपर्ट का कहना है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है. बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है. अगर समय रहते रोजगार के अवसर नहीं सृजन किए गए तो अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में EPFO की तरफ से सरकार को राहत भरी खबर मिली है.

ईपीएफओ (EPFO) की डेटा के मुताबिक पिछले 15 महीने में करीब 73 लाख लोगों को नौकरी मिली है. केवल नवंबर (2018) महीने में 7.32 लाख लोगों को नौकरी मिली है. उस महीने में जॉब क्रियेशन रेट 48 फीसदी रही थी. बात अगर नवंबर 2017 की करें तो केवल 4.93 लाख लोगों को नौकरी मिली थी. EPFO की पेरोल डेटा के मुताबिक सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के बीच 73.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है.

रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 के लिए जो अनुमान जारी किए गए थे, उससे कम लोगों को नौकरी मिली. अनुमान 8.27 लाख था, लेकिन नौकरी केवल 6.66 लाख लोगों को ही मिली. सितंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच जितनी नौकरी का अनुमान लगाया गया था उससे करीब 16.4 फीसदी कम नौकरियां पैदा हुईं.

भारत की औद्योगिक गतिविधियों के निकट अवधि में मंद रहने की संभावना: रिपोर्ट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारत में औद्योगिक गतिविधियां निकट अवधि के दौरान मंद रह सकती हैं। इसकी वजह सुस्त घरेलू मांग, कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वर्ष 2019 के आम चुनावों के परिणामों को लेकर व्यवसायों के बीच जारी अनिश्चितता है। यह अनुमान एक रिपोर्ट में लगाया गया है।डीएंडबी इकोनॉमी फोरकॉस्ट के मुताबिक लक्ष्य के मुकाबले कर संग्रह में महत्वपूर्ण कमी के बीच सरकार की ओर से निवेश कम किए जानें की चिंताओं के कारण औद्योगिक गतिविधियों के निकट अवधि में मंद रहने का अनुमान है। डन एंड ब्रॉडकास्ट (डीएंडबी) का अनुमान है कि दिसंबर 2018 के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स में 1.5 से 2 फीसद तक की कमी आएगी।केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक नवंबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 17 महीने के निचले स्तर के साथ 0.5 फीसद पर आ गई थी।

चॉकलेट के बाद यह दिग्गज कंपनी बेचेगी ऊंटनी का दूध, हैरान करने वाले हैं फायदे

मुंबई : प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल (Amul) ने पहली बार गुजरात के बाजारों- गांधीनगर, अहमदाबाद और कच्छ में ऊंटनी के दूध को बाजार में उतारा है. इस प्रमुख डेयरी कंपनी ने कहा कि इस दूध को कच्छ क्षेत्र से प्राप्त किया गया है. ऊंट का दूध 50 रुपये की कीमत पर 500 मिलीलीटर की पीईटी बोतलों में उपलब्ध होगा, और इसे ठंडा रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह दूध तीन दिन तक ही यूज करने लायक रह पाता है.

ग्राहकों से मिली थी अच्छी प्रतिक्रिया

अमूल ने इससे पहले ऊंटनी के दूध की चॉकलेट पेश की थी जिसे ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. कंपनी ने कहा कि ऊंटनी के दूध को पचाना आसान है और इसके कई लाभ होने के साथ-साथ यह काफी फायदेमंद है. कंनंनी ने बताया इसमें इंसुलिन जैसे प्रोटीन अधिक मात्रा है जिससे यह मधुमेह के व्यक्तियों के लिए फायदेमंद रहता है. आगे पढ़िए ऊंटनी के दूध को नियमित रूप से पीने से होने वाले फायदों के बारे में.

मस्तिष्क का विकास

ऊंटनी के दूध का नियमित सेवन करने वाले बच्चों का मस्तिष्क सामान्य बच्चों की तुलना में तेजी से विकसित होता है. इतना ही नहीं उसकी सोचने-समझने की झमता भी सामान्य से बहुत तेज होती है. ऊंटनी का दूध बच्चों को कुपोषण से बचाता है.

हड्डियों को मजबूत करें

ऊंटनी के दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं. इसमें पाया जाने वाला लेक्टोफेरिन नामक तत्व कैंसर से भी लड़ने में मददगार होता है. इसे पीने से खून से टॉक्सिन्स भी दूर होते हैं और यह लिवर को साफ करता है. पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम पाने के लिए भी ऊंटनी के दूध का सेवन करते हैं.

सुपाच्य

ऊंटनी का दूध तुरंत पच जाता है. इसमें दुग्ध शर्करा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर ,लैक्टिक अम्ल, आयरन, मैग्निशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन सी, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज आदि तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर को सुंदर और निरोगी बनाते हैं.

डायबिटीज में आराम दें

ऊंटनी का दूध डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण है. ऊंटनी के एक लीटर दूध में 52 यूनिट इंसुलिन पाई जाती है. जो कि अन्य पशुओं के दूध में पाई जाने वाली इंसुलिन से काफी अधिक है. इंसुलिन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है. इसका सेवन करने से सालों का मधुमेह महीनों में ठीक हो जाता है.

स्किन प्रॉब्लम को दूर करें

बीमारियों में राहत देने के अलावा ऊंटनी का दूध का सेवन स्किन में भी निखार लाता है. ऊंटनी के दूध में अल्फा हाइड्रोक्सिल अम्ल पाया जाता है. यह त्वचा को ग्लो देता है. यही कारण है कि ऊंटनी के दूध का सेन सौंदर्य संबंधी प्रोडक्ट तैयार करने में भी किया जाता है.

संक्रामक रोगों से बचाव

ऊंटनी के दूध में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा मं पाए जाते हैं. इसमें पाया जाने वाला एंटीबॉडी शरीर को संक्रामक रोग से बचाता है. यह गैस्ट्रिक कैंसर की घातक कोशिकाओं को रोकने में भी मदद करता है. यह शरीर में कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है जो संक्रामक रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी के रूप में काम करती हैं.

गणतंत्र दिवस की तैयारी के चलते दिल्ली में ये रूट रहेंगे बंद, जानें ट्रैफिक डायवर्जन

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में परेड की तैयारी चल रही है. तैयारी की खातिर कई रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. सेंट्रल और नई दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. रोड बंद करने और ट्रैफिक डायवर्ट करने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपको पहले से रोड के बारे में जानकारी होगी तो ज्यादा पेरशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. आपको उन रास्तों के बारे में बता रहे हैं जिन रास्तों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

सहयोगी वेबसाइट ज़ीबिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार आज (बुधवार) सुबह 6 बजे से परेड खत्म होने के समय तक विजय चौक से इंडिया गेट के बीच राजपथ पर ट्रैफिक की एंट्री बंद रहेगी. रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड से राजपथ की क्रॉसिंग के दोनों ओर मंगलवार रात 11 बजे से ही ट्रैफिक की एंट्री बंद कर दी गई है. इंडिया गेट के आउटर सर्कल को भी सुबह 9 बजे से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है. सुबह 10 बजे से तिलक मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर भी ट्रैफिक की एंट्री रोक दी गई है. हालांकि, क्रॉस ट्रैफिक चलता रहेगा, लेकिन जब परेड नजदीक पहुंच जाएगी, तो भगवानदास रोड, तिलक मार्ग डब्ल्यू पॉइंट, आईटीओ क्रॉसिंग, दिल्ली गेट क्रॉसिंग और दरियागंज में पुराने फुट ओवरब्रिज की क्रॉसिंग से क्रॉस ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाएगा.दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, परेड सुबह 9:50 बजे विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ, इंडिया गेट आउटर सर्कल, तिलक मार्ग, आईटीओ, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट और दरियांगज के नेताजी सुभाष मार्ग से होती हुई सुबह करीब 11 बजे लाल किला मैदान में पहुंचेगी. परेड जहां-जहां से गुजरेगी, उस वक्त उन इलाकों की सड़कों पर आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.

इन समय में निकलने से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि लोग पहले से ही प्लानिंग करते हुए घर से निकलें और सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच परेड के रूट से बचें. परेड के चलते ट्रैफिक डायवर्जन के कारण दूसरे रास्तों पर भी ट्रैफिक का लोड ज्यादा रहने की संभावना है. ऐसे में आईटीओ, विकास मार्ग, मथुरा रोड, भैरों रोड, सराय काले खां से आईएसबीटी के बीच रिंग रोड, रिंग रोड बाइपास, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अजमेरी गेट, डीडीयू मार्ग, कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मदर टेरेसा क्रिसेंट, सरदार पटेल मार्ग, धौला कुआं, पंचशील रोड, वंदे मातरम मार्ग, पंचकुइयां रोड, अरविंदो मार्ग, लोदी रोड पर भी जाम लग सकता है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों को अजमेरी गेट की तरफ से और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों को रिंग रोड बाईपास से यमुना बाजार हनुमान मंदिर और एसपीएम मार्ग से होते हुए जाने की सलाह दी गई है. कश्मीरी गेट बस अड्डे आने-जाने वालों को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

Budget 2019 : चाहिये सैलरी और पेंशन, बजट से पहले वकीलों की है ये 10 मांगें

नई दिल्ली: देशभर के वकीलों की सबसे बड़ी नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आम बजट से पहले मोदी सरकार के सामने 10 बड़ी मांगें रख दी हैं. साथ ही पूरे देश में मौजूद करीब 13 लाख से ज्यादा वकीलों के लिए हर वार्षिक बजट में 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि दिए जाने की मांग की है. बीसीआई का कहना है कि मोदी सरकार 31 जनवरी से पहले उनकी सभी मांगों को पूरा करे, वरना देशभर के वकीलों की तरफ से एक बड़ा विरोध-प्रदर्शन होगा, जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है.बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का कहना है

कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2014 को गांधी नगर में बीसीआई की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया था कि अगर वे प्रधानमंत्री बने तो देशभर के वकीलों के लिए बजटीय प्रावधान करेंगे, ताकि उनका उत्थान हो सके. उनके पीएम बनने के बाद हमने सदानंद गौड़ा, जो उस वक्त कानून मंत्री भी थे से मुलाकात कर यह बातें सामने रखी थीं, लेकिन अभी तक काई भी कदम नहीं उठाया गया है.

यह उठाई गई मांगें...

1. देशभर के वकीलों और परिजनों के लिए 20 लाख से अधिक तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाए.2. मेडिक्लेम देश-विदेश के बेहतर अस्पतालों में वकीलों को हर तरह की बीमारी का मुफ्त इलाज कराया जाए. इसके लिए वकीलों को स्पेशल कार्ड मुहैया कराया जाए.3. नए वकीलों को वजीफे के रूप में कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएं.4. बुजुर्ग वकीलों के लिए पेंशन और वकीलों के असामयिक निधन पर उनके आश्रितों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए.5. देश की सभी बार एसोसिएशन को उचित बिल्डिंग, ठहरने की व्यवस्था, बैठने की सुविधाएं लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और इंटरनेट टॉयलेट सहित उपलब्ध होनी चाहिए. महिला वकीलों को भी उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएं.6. संसद द्वारा वकील संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया जाए.7. सभी वकीलों को ब्याज मुक्त होम लोन उपलब्ध कराया जाए. 8. लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में संशोधन ैर उचित बदलाव किए जाएं. 9. वे सभी कानून जो रिटायर जजों और न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी/अधिकरणों के सदस्य, फोरम/अथॉरिटी के कमिशनर नियुक्त करने का अधिकार देते हैं, उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाए ताकि काबिल भी इन पदों पर नियुक्त हो सकें.10. किसी भी वकील की असामयिक मौत (65 साल से कम) पर उनके परिजनों/आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए.इसके साथ ही बजट से पहले काउंसिल की तरफ से पीएम मोदी से मांग की गई है कि आम बजट 2019-20 में देशभर के वकीलों के लिए अलग से हर साल 50 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं. इसके साथ ही सुझाव दिया गया है

कि इस राशि को एक सा सदस्यीय ट्रस्ट/कमेटी के जरिये खर्च किया जाए जिसका नेतृत्व एडवोकेट जनरल करें. काउंसिल ने पीएम को लिखे पत्र में उनसे उम्मीद जताई है कि वे इन मांगों पर शीघ्र विचार करें ताकि उनकी शिकायतों को हल किया जा सके. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि वकीलों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं.

लगातार 6 दिन बढ़ने के बाद थमी पेट्रोल और डीजल की कीमत, जानें आज का रेट

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमत में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ. मंगलवार को इसकी कीमत में 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी. मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल के दाम में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी. देश की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली मुंबई में भी तेल की दामों में वृद्धि हुई थी.

बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमश= 71.27 रुपये और 65.90 रुपये है. वहीं, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के भाव क्रमश= 73.99 रुपये, 73.36 रुपये और 76.90 रुपये प्रति लीटर हैं. इसी तरह तीनों महानगरों में डीजल की कीमत 69.62 रुपये, 67.68 रुपये और 69.01 रुपये प्रति लीटर है. आपको बता दें कि मंगलवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के भाव में 13 पैसे जबकि चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी. वहीं, डीजल के दाम दिल्ली और कोलकाता में 19 पैसे और जबकि मुंबई में 20 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में मंगलवार को पेट्रोल के भाव क्रमश= 71.27 रुपये, 73.36 रुपये, 76.90 रुपये और 73.99 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए. चारों महानगरों में डीजल की कीमतें नई वृद्धि के बाद क्रमश= 65.90 रुपये, 67.68 रुपये, 69.01 रुपये और 69.62 रुपये प्रति लीटर था.अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार कच्चे तेल में नरमी आई है, हालांकि ब्रेंट क्रूड का भाव अभी तब 62 डॉलर प्रति डॉलर से ऊपर चल रहा है और डब्ल्यूटीआई भी 53 डॉलर प्रति बैरल के उच्च भाव पर बना हुआ है. कमोडिटी विश्लेषक बताते हैं कि चीन की मंदी की रिपोर्ट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार थमने का अंदेशा है

मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने दुनिया की टॉप-100 में बनाई जगह, 95 पायदान की छलांग

नई दिल्ली: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस रिटेल ने 95 पायदान की छलांग लगा कर खुदरा कारोबार में सबसे अधिक कमाई करने वाली दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में अपनी जगह बना ली है. एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं और रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं और फैशन एवं लाइफस्टाइल वस्तुओं के कारोबार में उल्लेखनी वृद्धि का कंपनी की इस उपलब्धि में बड़ा हाथ है.

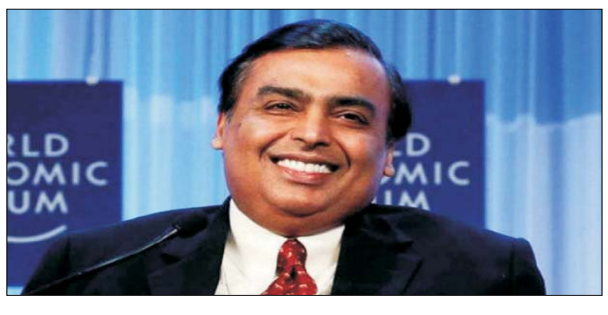

डेलॉयट की 'ग्लोबल पॉवर्स ऑफ रिटेलिंग 2019' की 250 खुदरा कंपनियों की वैश्विक सूची में रिलायंस रिटेल 94वें पायदान पर पहुंच गई है. यह पिछले साल की सूची में रिलायंस रिटेल की रैंकिंग में 95 पायदान की बड़ी उछाल है. इस सूची में यह भारत की पहली कंपनी है और इसे वर्ष 2018 में इसमें शामिल किया गया. डेलॉयट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 250 कंपनियों की रैंकिंग की है. इसके लिए कंपनियों के वित्त वर्ष 2017 के खुदरा राजस्व को आधार माना गया है. भारतीय कंपनियों के मामले में, मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष को आधार माना गया है.

डेलॉयट ने कहा कि रिलायंस रीटेल ने वित्त वर्ष 2016 में सबसे तेजी से उभरती हुयी खुदरा कंपनियों की सूची में जगह बनाई थी. यह सूची पिछले साल जारी की गई थी. रिलायंस रिटेल ने अपनी वृद्धि को जारी रखते हुये वित्त वर्ष 2017 में अपना राजस्व करीब दोगुना पहुंचा दिया. इसके चलते शीर्ष 250 खुदरा कंपनियों की सूची में वह 95 अंक की छलांग लगाकर 94वें पायदान पर पहुंच गई है.

इस सूची में पहले पायदान पर वॉलमार्ट, दूसरे पर कॉस्टको और तीसरे पर क्रोगर है. वहीं, अमेजन दो स्थान की छलांग लगाकर चौथे पायदान पर पहुंच गई है. सूची में पहले 10 स्थान में से सात पर अमेरिकी कंपनियां है. जर्मनी की श्वार्ज और एल्दी एन्काफ क्रमशः पांचवें और 9वें स्थान पर है. ब्रिटेन की टेस्को एक स्थान उठ कर 10वें नंबर पर आ गयी है. रपट के अनुसार सबसे तेजी से वृद्धि कर रही शीर्ष 50 कंपनियों में रिलायंस रिटेल का 6ठा स्थान है. कंपनी ने 2012-17 के दौरान कारोबार में साल-दर-साल 44.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की.2016-17 में वृद्धि 105 प्रतिशत से अधिक थी.

लोकसभा चुनाव 2019 : क्या रघुराम राजन से कांग्रेस तैयार करवाएगी अपना विजन डॉक्यूमेंट?

नई दिल्ली: अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी जारी है. ऐसे में खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए पूर्व RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) गवर्नर रघुराम राजन की मदद लेगी. कांग्रेस चाहती है कि वे वर्तमान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पार्टी की रणनीति बनाने में मदद करें. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेरोजगारी और कृषि के मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं. ऐसे में वे चाहते हैं कि रघुराम राजन भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा इन दो मुद्दों पर पार्टी की मदद करें.

हाल ही में राहुल गांधी दुबई के दौरे पर थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस दौरान राहुल गांधी की रघुराम राजन से बात हुई थी. कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि रघुराम राजन ने बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने का रास्ता भी बताया है. ऐसे में राहुल गांधी चुनावी अभियान में बेरोजगारी के मुद्दों पर इस रिपोर्ट की मदद लेंगे.रघुराम राजन क्रशासनकाल में अगस्त 2012 से सितंबर 2013 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार थे. उसके बाद उन्हें RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया. उन्हें सितंबर 2013 में ही रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था. वे इस पद पर सितंबर 2016 तक रहे. इस दौरान कई मौकों पर उन्होंने वर्तमान सरकार के सुझावों को सिरे से नकार दिया था. मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी कि उनकी और सरकार की बन नहीं रही है.आखिरकर 4 सितंबर 2016 को कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने सेवा विस्तार लेने से इनकार कर दिया था. उनकी जगह पर उर्जित पटेल को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था. उन्होंने 11 दिसंबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शक्तिकांत दास को 12 दिसंबर 2018 को RBI का नया गवर्नर नियुक्त किया गया.

बता दें, सरकार के साथ मतभेद की खबरों को लेकर रघुराम राजन ने नकारते हुए कहा था कि वे निजी कारणों से इस पद पर नहीं बने रह पाए. उन्होंने कहा था कि वे वापस शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते थे और परिवार की वजह से शिकागो लौटने का फैसला लिया. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है.

एकबार पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा था कि मुझे तो अर्थव्यवस्था के बारे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रघुराम राजन फाइल लेकर आते हैं और मुझे सबकुछ सिखा कर चले जाते हैं. इसके बाद मेरे लिए सबकुछ समझना और फैसले लेना आसान हो जाता है.

संपादकीय

चुनावी पण्राली

क्सफेम इंटरनेशनल ने भारत में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष पूंजीवाद का स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि हमने जो मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाई, उस व्यवस्था में ऐसा ही होता है। हमारी चुनावी राजनीति भी पूंजीपतियों पर निर्भर रहने के लिए अभिशप्त है। चुनावी पण्राली इतनी अधिक खर्चीली हो गई है कि सांसद और विधायक के चुनाव की बात छोड़ दीजिए, एक पार्षद को भी अपने चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऑक्सफेम की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के शीर्ष नौ अमीरों की संपत्ति 50 प्रतिशत गरीब आदमी की संपत्ति के बराबर है। इसी तरह, भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास देशकी कुल संपत्ति का 77.4 फीसद हिस्सा है और 2018 से 2022 के बीच भारत में रोजाना 70 नये करोड़पति बनेंगे। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि पूंजी से पूंजी बनती है। जाहिर है कि जिसके पास पूंजी नहीं है, वह इस खेल में पिछड़ जाता है। बस यहीं से आर्थिक असमानता की शुरुआत होती है। दरअसल, मानव सभ्यता के विकास-क्रम में असमानता एक शाश्वत सत्य है। कार्ल मार्क्स से लेकर लास्की जैसे अनेक बौद्धिकों और विचारकों ने असमानता और विशेषकर आर्थिक असमानता को समाप्त करके समानता पर आधारित समाज की स्थापना का विचार दिया है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि आय की विषमता को कम नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचने लगे तो अमीर और गरीब की बढ़ती खाई को पाटा जा सकता है। इसके लिए सरकारों को ईमानदारी से प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहा कि बीते साढ़े चार वर्षो में 5 लाख 78 हजार करोड़ रुपये हमारी सरकार ने किसी को घर, किसी को गैस सिलेंडर, किसी को अनाज खरीदने और किसी को पढ़ाई के लिए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किये हैं। इस अच्छी पहल के जरिये सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जन तक पहुंचने लगा है। इससे सरकारी धन के बंदरबांट की गुंजाइश खत्म हो गई। इसी तरह अमीरों से उनकी सम्पत्ति पर अतिरिक्त कर वसूलना चाहिए। आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिएसरकार को मजबूती के साथ व्यवस्था में बदलाव लाना होगा।

याचिका खारिज

न्यायालय द्वारा दागी नेताओं को पार्टियों द्वारा टिकट न देने से रोकने की याचिका खारिज करना स्वाभाविक है। किसी पर अपराध या भ्रष्टाचार का आरोप लगने मात्र को दोष मान लिया जाना न्याय की सोच नहीं हो सकती। न्याय का मूल सिद्धांत है कि कोई दोषी छूट जाए इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी निदरेष को सजा मिले यह उचित नहीं। इसलिए न्यायपालिका किसी को सजा देने के पहले उसके अपराधों से संबंधित सारे साक्ष्यों का गहन परीक्षण करती है। आरोपित को अपने बचाव का पूरा अवसर मिलता है। न्यायपालिका अगर राजनीतिक दलों को यह आदेश दे कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को उम्मीदवार न बनाएं जिन पर किसी तरह के अपराध का आरोप हो तो यह उसके अपने ही सिद्धांत के विरु द्ध होगा। वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2013 में ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाने पर रोक लगा दी थी जो या तो गिरफ्तार है, जिसे दो साल से ज्यादा की सजा मिल चुकी है। यह आदेश ही पर्याप्त है। इसे ज्यादा खींचना न उचित होगा और न व्यावहारिक ही। सार्वजनिक जीवन में कई कारणों से व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। आंदोलनों के दौरान भी आपराधिक धाराओं में ही मुकदमा दर्ज होता है। कोई न्याय की मांग के लिए आंदोलन करे उसे भी केवल इस आधार पर अपराधी मान लिया जाए कि उस पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, यह कहां का न्याय होगा? हालांकि न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए ज्यादा विस्तार से ये बातें नहीं कही है। इस पर लंबे समय से बहस होती रही है और होनी भी चाहिए। अपराध करने वालों के चुनाव जीतकर सत्ता का हिस्सा बनने के अनेक दुखद उदाहरण मौजूद हैं। इस स्थिति के अंत के लिए निस्संदेह गंभीर प्रयास की जरूरत है। पर पिछले वर्षो में यह काफी कम हुआ है। इसमें न्यायिक तथा चुनाव आयोग की सक्रियता की भी भूमिका रही है। किंतु यह इनसे ज्यादा सामाजिक जागरण और राजनीतिक नैतिकता का विषय है। राजनीति में ऐसे लोग भी हैं, जिन पर अपराध के गंभीर मामले भले दर्ज न हों, पर उनके अपराधी होने का ज्ञान समाज को है। अगर समाज ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करने लगे तो राजनीतिक दल इनको उम्मीदवार बनाने से स्वयं बचने लगेंगे।

सत्संग

''मैं''

गर ये शरीर उसी मिट्टी का बना है, जिस पर हम चलते हैं, तो फिर हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? हम पूरी धरती को अपने हिस्से के रूप में कैसे अनुभव कर सकते हैं? जब आपका जन्म हुआ था, आप का कद कितना था? अब कितना है? इस बीच उसके बढ़कर विकसित होने के लिए आपने क्या किया? आप कहेंगे, ''उसे खाना दिया'। लेकिन आपको भोजन कहां से मिला? इसी माटी से। आपकी खाई हरेक चीज-साग-सब्जी और अनाज इसी माटी से ही तो तैयार हुए। अगर आप सामिष खाने वाले हैं तो आपकी खाई हरेक बकरी और मुर्गी भी तो इसी माटी से उपजी वस्तुओं को खाकर बड़ी हुई थी, और फिर आपकी भूख बुझाई थी। जैसे भी हो, कुल मिलाकर मूल रूप से इसी माटी से आपका शरीर बना है। ज्यों-ज्यों आपके शरीर में माटी जुड़ती गई आपने उसे ''मैं' कहकर अपना लिया। एक लोटे में जल रखा है। क्या वह जल और आप एक हैं? आप कहेंगे ''नहीं'। उस जल को लेकर पी लीजिए। जब वह आपके शरीर में मिल गया उसे क्या कहेंगे? अब वह ''आप' बन गया न? मतलब यह है कि आपके अनुभव की सीमा में जो आ जाता है, उसी को आप ''मैं' के रूप में महसूस करेंगे। जब तक वह बाहर है आप समझते हैं, वह अलग है और आप अलग हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि बाहर वाले पानी, माटी, हवा और ताप से ही आपका निर्माण हुआ है? जब वे आपका एक हिस्सा बन गए उन्हें अलग-अलग करके देखना संभव नहीं रहा। कुल मिलाकर उसे ''मैं' की पहचान दे दी आपने। आपके पुरखे कहां गए? चाहे उन्हें दफनाया गया हो या जलाया गया हो, वे इसी माटी में समा गए हैं। इस बात को न भूलें कि उन्हीं के ऊपर आप रोज कदम रखते हुए चलते हैं। आप भी आखिर में कहां जाने वाले हैं? आपके मूल तत्व रूपी इसी माटी के ही अंदर। थोड़ी-सी माटी आपका स्वरूप बनकर सांस ले रही है। और कुछ माटी आपके बाग में ऊंचे पेड़ के रूप में बढ़कर खड़ी है और थोड़ी मोटी कुर्सी बन गई है जिस पर आप बैठे हैं। इसी माटी-चक्र की प्रक्रिया में आम, नीम, इमली, फूल, केंचुआ, मनुष्य अनेक और भिन्न-भिन्न अवतार ले रही है, और लेने वाली है। घड़े में रखें या छोटे कलश में, उसे आप पानी ही तो कहेंगे? यही दलील आप पर भी लागू होती है न? माना कि इकठ्ठा किए गए बरतन अलग-अलग हैं, लेकिन उनकी बनावट का मूल तत्व यही माटी है न?

''निर्धनों का देश घोषित'

चंद रोज पहले ही रामलीला मैदान में भाजपा के दस हजार कार्यकर्ताओं के बीच खुद मोदी ने यह कह कर कि ''मोदी की आस में मत रहो कि वह आकर सब ठीक कर देगा'। यही स्वीकारा था कि मोदी अब अकेले विपक्ष के तूफान से भाजपा के जहाज को बचाने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर अनेक तोहमतें लगाई और फिर यह सवाल दागा कि क्या आप ऐसा प्रधान सेवक चाहेंगे? कल तक राहुल की भौंडी नकल उतारने वाले अब जैसे खुद राहुल को पीएम पद के लिये प्रस्तावित कर रहे थे! वे जब कई मृतात्माओं का आह्वान करते हुए कह रहे थे कि यदि पटेल प्रधानमंत्री होते..यदि 2004 में अटल बिहारी फिर आ जाते..तो भारत कुछ और होता, तब वे प्रकारांतर से ईर से सिर्फ यह प्रार्थना करते लग रहे थे।

सतीश पेडणोकर

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी के आह्वान पर मोदी के खिलाफ समूचे राष्ट्रीय विपक्ष की विशाल सभा से फिर एक बार 2019 के चुनाव के मद्देनजर जनमानस में चल रही व्यापक उथल-पुथल का साफसंकेत मिला। वोटों के शुद्ध गणित के आधार पर ही कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का मोदी अध्याय अब लगभग अपने समापन पर आ गया है। मोदी जी की सीबीआई की रस्सी के सांप ने वास्तव में राजनीतिक हलकों में कोई नया भ्रम या डर पैदा नहीं किया, बल्कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया। 2019 के चुनाव का जो समीकरण अब साफदिखाई देता है वह है मोदी+सीबीआई+ईडी+आईटी वनाम अन्य सभी सियासी दल (इनमें एनडीए के कुछ दल भी शामिल हैं)। अब यह कहने में कोई हिचक नहीं कि 2019 में मोदी का लौटना तार्किक असंभवता के स्तर तक, मसलन एक वृत्ताकार चौकोर को पाने के स्तर तक चला गया है। चंद रोज पहले ही रामलीला मैदान में भाजपा के दस हजार कार्यकर्ताओं के बीच खुद मोदी ने यह कह कर कि ''मोदी की आस में मत रहो कि वह आकर सब ठीक कर देगा'। यही स्वीकारा था कि मोदी अब अकेले विपक्ष के तूफान से भाजपा के जहाज को बचाने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर अनेक तोहमतें लगाई और फिर यह सवाल दागा कि क्या आप ऐसा प्रधान सेवक चाहेंगे? कल तक राहुल की भौंडी नकल उतारने वाले अब जैसे खुद राहुल को पीएम पद के लिये प्रस्तावित कर रहे थे! वे जब कई मृतात्माओं का आह्वान करते हुए कह रहे थे कि यदि पटेल प्रधानमंत्री होते..यदि 2004 में अटल बिहारी फिर आ जाते..तो भारत कुछ और होता, तब वे प्रकारांतर से ईर से सिर्फ यह प्रार्थना करते लग रहे थे कि काश, 2019 में मैं फिर से जीत जाता!

''टेलिग्राफ' अखबार ने सुर्खी लगाई-''मोदी ने मोदी को पीएम बनाने की शपथ ली'। पराजित मन का यह आर्तनाद सचमुच बहुत करुण था! अभी मोदी उन्हें खींच रही भंवर से उबरने के लिए जिस प्रकार हाथ-पैर मार रहे हैं, उसमें डूबने से बचने के बजाय वे और तेजी से डूबने की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। उनके पास भंवर के खत्म होने तक प्रयत्नहीन, हल्के रह कर टूटी नाव से ही चिपक कर ऊपर-ऊपर चक्कर काटते रहने का हुनर ही नहीं है। वे अभी भी सीबीआई, सीवीसी, ईडी,आईटी के डंडों से सबको देख लेने के करतबों में लगे हुए हैं। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पद पर बहाल करके उनके खिलाफसभी फर्जी आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रक्रिया और न्याय के बीच संतुलन का खेल भी खेला और आलोक वर्मा के भविष्य की डोर सेलेक्शन कमेटी को सौंप दी। अपने गहराते संकट का अभास कर मोदी के लिये उचित था कि सुप्रीम कोर्ट की राय से सही सबक लेते हुए थोड़ा शांत हो जाते। लेकिन जस्टिस सीकरी के सहयोग से उन्होंने आलोक वर्मा को हटाने का जो काम किया उस पर सीवीसी की रिपोर्ट की जांच करने वाले जस्टिस एके पटनायक तक कह रहे हैं कि आलोक वर्मा के साथ न्याय नहीं हुआ, सेलेक्शन कमेटी ने हड़बड़ी में,अर्थात् मोदी के दबाव में निर्णय लिया। इसी बात को पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने भी कहा है कि आलोक वर्मा को प्राकृतिक न्याय के अधिकार से वंचित किया गया है। राफेल मामले पर मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राहुल ने इस विषय में सरकार की परीक्षा के लिये सिर्फ दो सवाल पेश किये हैं- पहला,अनिल अंबानी को किसने ठेका दिलाया? दूसरा, क्या रक्षा मंत्रालय ने मोदी के किये सौदे पर आपत्ति की थी? किसी में हिम्मत नहीं कि वे इन सवालों का सीधा जवाब दें। ऊपर से निर्मला सीतारमण की यह अनोखी उक्ति-बोफोर्स में कमीशनखोरी कांग्रेस को ले डूबी थी और राफेल मोदी की डूबती नौका को बचायेगा!चुनावी रणनीति के लिहाज से निर्धनों के लिये आनन-फानन में लाया गया आरक्षण विधेयक भी एक और आत्महंता कदम साबित होगा। निर्धनों सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण का झुनझुना लगता है; जैसे चुनावी मौसम के तनावों से बचने के लिये भाजपा के लोगों के खेलने के लिये तैयार किया गया है। भारत के 95 प्रतिशत परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रु पये से कम है। इसके अलावा, घर के क्षेत्रफल के मामले में भी 90 प्रतिशत परिवारों के पास आरक्षण विधेयक में तय सीमा से छोटे घर हैं। तब सवाल रह जाता है कि निर्धन कौन नहीं?

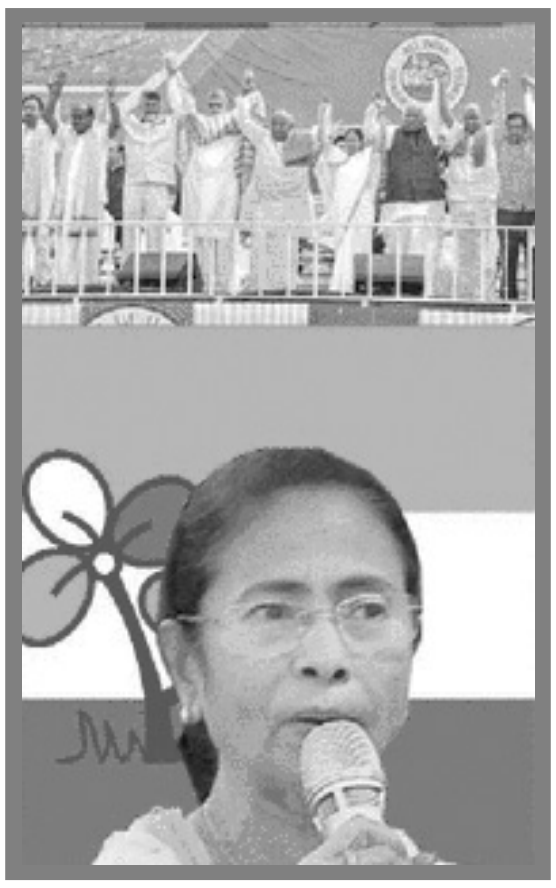

कोटे का मतलब क्या है जब सिर्फ5 प्रतिशत परिवारों को ही इसके बाहर रखा गया है? कुल मिला कर इस विधेयक के बाद भारत ''निर्धन नागरिकों' का देश कहलाने लगेगा। कहां ये चले थे, इस देश को समृद्ध और विश्वगुरु बनाने, और जाते-जाते इसे ''निर्धनों का देश घोषित' कर गये! जहां तक इसके चुनावी प्रभाव का सवाल है, इसने सभी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ों के बीच मोदी और आरएसएस की छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जो लोग भी इस आरक्षण के शिगूफे पर हांक रहे हैं कि इसका 2019 के चुनाव पर भारी असर पड़ेगा, वे पेशेवर गपोड़ी हैं। वे सचमुच जनता को महामूर्ख समझते हैं।मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाल के चुनावों में भाजपा के मतों में क्रमश: 12,16 और 16 प्रतिशत की गिरावट हुई। यूपी के सारे उपचुनाव बताते हैं कि वहां भी उसके मतों में 12 प्रतिशत से अधिक की गिरावट होगी। अर्थात् भाजपा को किसी हाल में 30 प्रतिशत से ज्यादा मत नहीं मिलेंगे। सपा-बसपा के कुल मिला कर 40 प्रतिशत वोट पक्के हैं। मतलब यूपी में भाजपा को एक-एक सीट का लाला पड़ सकता है। मोदी जी के प्रस्थान के लिये इतना ही काफी है। विपक्ष की कोलकाता रैली ने इसी प्रक्रिया के अखिल भारतीय स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है। बहरहाल, पूंजीवादी जनतंत्र एक वर्ग का अन्य वर्गों पर जितना भी अबाध और स्वेच्छाचारी शासन क्यों न हो, यह जीवन का कोई रूढ़िगत रूप कतई नहीं है। यह गोमाता की सेवा और मंदिर-मस्जिद के लिये मर-मिटने वाले जुनूनी वीरों तथा पुराण कथाओं में धूनी रमा कर आधुनिक विज्ञान को धत्ता बताने वालों का शासन नहीं होता है। मार्क?स के शब्दों में यह अपने मूल अर्थ में ''पूंजीवादी समाज में क्रांति का सामाजिक रूप मात्र होता है।..(इसमें) स्वत: प्रवहमान तत्वों का निरंतर परिवर्तन और अंतर्विनिमय होता हैं,अंतिम बात यह है कि इसमें भौतिक उत्पादन जिसे नई दुनिया को अपना बनाना होता है, की प्रचंड, युवावस्था जैसी गति ऐसी है कि उसे पुराने प्रेत-जगत का उन्मूलन करने का न तो समय है और न अवसर।'(लेखक के निजी विचार हैं)

चलते चलते

सफाई को लेकर दिमागी सम्पन्नता

किन यादन में खोयौ भयौ ऐ? -चचा, सुबह-सुबह इतना विषैला अंधेरा देख कर गांव की याद आ रही है। तो एक गीत लिख डार! अब गाम वैसे नायं बचे, जैसै तिहारी कबतान में आमैं। -चचा, मैं अपने गांव की यादों में नहीं हूं। आठ साल पहले मेघालय के जिस गांव में गया था, उसकी याद आ रही है। हाल के किसी अखबार में उसकी तस्वीर देखी तो स्मृतियों की रील घूम गई। संसार का सबसे स्वच्छ गांव, मावलिन्नांग। इस गांव में बहुत सम्पन्न लोग रहते हों, ऐसा नहीं है। खूब गरीबी है, लेकिन सफाई को लेकर दिमागी सम्पन्नता है। बहुत शानदार झाड़ुएं और बांस के तिकोने गोलाकार कूड़ेदान बनाते हैं। बांस की बनी इतनी लंबी बैंच कि एक साथ पच्चीस आदमी बैठ जाएं। बांस का तो वहां कमाल का वास्तुशिल्प है। हम

अब गाम वैसे नायं बचे, जैसै तिहारी कबतान में आमैं। -चचा, मैं अपने गांव की यादों में नहीं हूं। आठ साल पहले मेघालय के जिस गांव में गया था, उसकी याद आ रही है। हाल के किसी अखबार में उसकी तस्वीर देखी तो स्मृतियों की रील घूम गई। संसार का सबसे स्वच्छ गांव, मावलिन्नांग। इस गांव में बहुत सम्पन्न लोग रहते हों, ऐसा नहीं है। खूब गरीबी है, लेकिन सफाई को लेकर दिमागी सम्पन्नता है। बहुत शानदार झाड़ुएं और बांस के तिकोने गोलाकार कूड़ेदान बनाते हैं।

बांस के इतने ऊंचे मचान पर सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़े कि वहां से बाग्लादेश भी दिखाई दे रहा था। पूरे गांव में हर पचास कदम पर कूड़ेदान लटके हुए थे। रास्ते एकदम साफ।-पेड़न ते पता नायं टूटें का?- क्यों नहीं टूटते! पत्ते दिख सकते हैं, लेकिन वहां मानव निर्मित एक तिनका भी पगडंडियों पर नहीं मिलेगा। हवा उनको उड़ा ले जाती है। मैं आपकी बहूरानी का एक मुक्तक सुनाता हूं, ''मैं भला कैसे बताऊं बता जमाने को? कितनी शिद्दत से लड़ा हूं, मै जां बचाने को!

डाल से टूट के पत्ते ने हवा से पूछा, क्या तुझे मैं ही मिला जोर आजमाने को!' प्रकृति टूटे पत्तों की रिसाइक्लिंग करके कहां पहुंचा देती है, कुछ पता नहीं चलता। प्रकृति की रिसाइक्लिंग से जल और भी स्वच्छ हो जाता है। क्या बताऊं चचा आपको! निर्मल झरने और उमनगोत जैसी स्वच्छ नदी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। फोटो दिखाऊंगा।

कम से कम बीस-पच्चीस फिट की गहराई तक पारदर्शी। नाव तैरे तो लगे जैसे कांच पर फिसल रही हो। आसमान साफरहता है। रात में झुंड के झुंड तारे टिमटिमाते हैं। मोदी के राज में सफाई आई है, लेकिन हमारे कचरे, ई-कचरे और अधकचरे दिमागों ने तो ढचरा ही बिठा दिया है।-सारी गड़बड़ी कुदरत के संग छेड़खानी ते है रई ऐ!

फोटोग्राफी...

प्रयागराज स्थित प्रसिद्ध नाग बासुकी मंदिर को इन दिनों कुंभ यात्रियों के दर्शनार्थ सजाया गया है।

सुभाष चन्द्र बोस

सवाधीनता संग्राम में नवीन प्राण फूंकने वाले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को ओडिशा (उड़ीसा) के कटक में हुआ था। उन्हें स्वामी विवेकानंद की आदर्शता और कर्मठता ने सतत आकर्षित किया। अपनी स्कूली पढ़ाई कटक के मिशनरी स्कूल व कॉलेजियट स्कूल से करने के बाद 1915 में प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां अंग्रेज प्रोफेसर ओटन द्वारा भारतीयों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने पर बोस को सहन नहीं हुआ और उन्होंने प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। इसको लेकर उन्हें को कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में 1917 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी की मदद से उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया। तभी से बोस के अंतर्मन में क्रांति की आग जलने लग गई थी और उनकी गिनती भी विद्रोहियों में की जाने लगी थी। दरअसल, बोस के पिता जानकी नाथ बोस पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गए थे और वे वोस को सिविल सेवा के पदाधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। पिता का सपना पूरा करने के लिए बोस ने सिविल सेवा की परीक्षा दी ही नहीं अपितु उस परीक्षा में चौथा पायदान भी हासिल किया। लेकिन उस समय बोस के मन में कुछ और ही चल रहा था। सन 1921 में देश में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के समाचार पाकर एवं ब्रिटिश हुकूमत के अधीन अंग्रेजों की हां-हूजूरी न करने की बजाय उन्होंने महर्षि अरविन्द घोष की भांति विदेशों की सिविल सेवा की नौकरी को ठोकर मारकर मां भारती की सेवा करने की ठानी और भारत लौट आए।स्वदेश लौट कर आने के बाद बोस अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चितरंजन दास से न मिलकर गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर वे महात्मा गांधी से जा मिलें। बेशक महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विचारधारा भिन्न-भिन्न थी, पर दोनों का मकसद एक ही था ''भारत की आजादी'। सच्चाई है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी ने ''राष्ट्रपिता' के संबोधन से संबोधित किया था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद नेताजी ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। कहा जाता है कि यह आयोग गांधीवादी आर्थिक विचारों के प्रतिकूल था। सन 1939 में बोस पुन: गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी को हरा कर विजयी हुए। जापान पहुंच कर बोस ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया से जापान द्वारा एकत्रित करीब चालीस हजार भारतीय स्त्री-पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन करना शुरू कर दिया। भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 1943 को ''आजाद हिन्द फौज' का गठन किया। सन 1943 से 1945 तक आजाद हिन्द फौज अंग्रेजों से युद्ध करती रही। अंतत: वह ब्रिटिश शासन को यह महसूस कराने में सफल रहे कि भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय ही ''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' और ''दिल्ली चलो' का नारा दिया। सक्रिय राजनीति में आने व आजाद हिन्द फौज की स्थापना से पहले बोस ने सन 1933 से 1936 तक यूरोप महाद्वीप का दौरा भी किया था। बोस ने कूटनीतिक व सैन्य सहयोग की अपेक्षा खातिर हिटलर से मित्रवत नाता भी कायम किया। साथ ही 1937 में ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी भी की और दोनों की अनीता नाम की एक बेटी भी हुई। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताईपे में विमान हादसे में हुई। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो विमान हादसे की बात को स्वीकार नहीं करता।

प्रियंका की राजनीति में एंट्री से कहीं नफा तो कहीं नुकसान

नई दिल्ली। प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बनाकर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने ट्रंप कार्ड खेला है। पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने के मकसद से प्रियंका को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस का दांव यकीनन चुनाव के मद्देनजर अहम है। इससे पार्टी को बड़े स्तर पर यूपी में फायदा मिलने की उम्मीद जगी है। मगर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कहीं ना कहीं ये रणनीति कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है।

कांग्रेस की सोची समझी रणनीति : सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी लगभग तीन दशक से यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाना पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि, कुछ दिनों पहले तक गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने पर कोई सुगबुगाहट नहीं थी। ये बात दीगर है कि बड़ा चेहरा होने के नाते प्रियंका को पार्टी में जिम्मेदारी दिए जाने की मांग लंबे अर्से से उठती रही है। मगर, अब कांग्रेस ने यूपी में फिर से वापसी करने के लिए अपना दांव खेल दिया है।

कांग्रेस को मिल सकते हैं ये फायदे : पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी अपने परिवार की सियासी विरासत को आगे ले जाएंगी। उनके पार्टी में सक्रि य हो जाने से महिलाओं का कांग्रेस की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। जो लोग आज भी इंदिरा गांधी को एक बेहतर शासक के तौर पर याद करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं प्रियंका में इंदिरा की झलक दिखाई देती है। अपने पिता की तरह जनता से सीधा संवाद प्रियंका की विशेषता है।

रॉबर्ट वाड्रा के बहाने कांग्रेस पर निशाना : प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हमेशा से ही भाजपा के निशाने पर रहे हैं। अभी तक पार्टी में कहीं भी उनका सीधा दखल आधिकारिक तौर पर नहीं था। लेकिन प्रियंका के महासचिव बन जाने से विपक्ष वाड्रा से जुड़े मामलों को लेकर हमले तेज कर सकता है। जिससे प्रियंका और पार्टी दोनों की जवाबदेही बढ़ेगी।

पार्टी में दो नेतृत्व : प्रियंका गांधी हमेशा से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की भूमिका को लेकर रणनीतिकार के तौर पर पर्दे के पीछे रही हैं। राहुल को पार्टी में अध्यक्ष पद तक ले जाने के पीछे भी कहीं ना कहीं बहन प्रियंका की सियासी समझ और फैसले भी वजह बने। लेकिन अब खुद उनके पार्टी में महासचिव जैसे बड़े पद पर आ जाने के बाद पार्टी में दोहरा नेतृत्व देखने को मिल सकता है, जो पार्टी के हित के खिलाफ जा सकता है।

सोनिया गांधी की संसदीय सीट संभालेंगी प्रियंका, रायबरेली से लड़ सकती है चुनाव

नई दिल्ली। आखिरकार वह फैसला हो ही गया, जिसका इंतजार कांग्रेस के एक बड़े तबके को लंबे समय से था। प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस ने पार्टी का महासचिव बनाकर बड़ा दांव खेल दिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। अब इस बात की अटकल तेज हो गई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां यानी सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। इस अटकल को बुधवार को तब तेजी मिली जब उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया।

सोनिया गांधी को 23 जनवरी को रायबरेली के दौरे पर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में यह दौरा रद्द कर दिया गया। इस वजह से भी प्रियंका गांधी के यहां से चुनाव लड़ने की अटकल एक बार फिर तेज हो गई। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा रायबरेली में लंबे समय से हो रही है। हाल ही में यह चर्चा तब और तेज हो गई थी जब रायबरेली के 8 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में प्रियंका वाड्रा की सहमति ली गई। यही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के चलते रायबरेली में उनकी सक्रियता कम हुई है। इसे देखते हुए पिछले कुछ समय से प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकल लगाई जाती रही है।रायबरेली और उसके पड़ोस में मौजूद अमेठी सीट नेहरू- गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। प्रियंका गांधी के लिए यह दोनों इलाके नए नहीं हैं। वे 1999 से कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रचार करती रही हैं। गौरतलब है कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से खराब रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तो रायबरेली में सोनिया गांधी की सक्रियता बहुत कम हो गई। ऐसे में प्रियंका वाड्रा रायबरेली में पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। प्रियंका रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहती हैं। वे दिल्ली में भी रायबरेली के कार्यकर्ताओं से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा बहुत सक्रिय थीं। उनकी सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के तबके यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका वाड्रा को सार्वजनिक मंच से कमांडर-इन-चीफ तक करार दे दिया था। 2017 में कांग्रेस और सपा के गठबंधन में भी प्रियंका का अहम रोल माना जाता है। बताया जाता है कि प्रियंका ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से बात कर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की जमीन तैयार की थी।

यहां इस बात का जिक्र दिलचस्प होगा कि प्रयागराज में गाहे-बगाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग करते रहे हैं। पार्टी का एक तबका प्रियंका वाड्रा में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि देखती रही है।

प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर बीजेपी बोली- कांग्रेस ने साबित किया राहुल गांधी हुए फेल

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला रास नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि इस फैसले से साफ है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं।

संबित पात्रा ने कहा कि आज ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से नकारे जाने के बाद बैसाखी परिवार से ही ढूंढी जा रही है।

उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया पूछ रहा है जवाहर लाल नेहरू से लेकर अब प्रियंका गांधी तक परिवार से नेता आ रहे हैं, लेकिन आगे कौन होगा। पात्रा ने कहा कि

आज पुष्टि हो गई है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं। वहीं बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हाराव का कहना है कि कांग्रेस का ये प्रियंका कार्ड चुनाव से पहले आता है और फेल हो जाता है। ये सिर्फ एक परिवार की राजनीति है।

कांग्रेस बोली- अब दम लगाकर लड़ेंगे

चुनावदूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अमेठी के नेता दीपक सिंह का कहना है कि इस मांग को काफी समय से उठाया जा रहा था, वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का शुक्रिया करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि कांग्रेस क्क में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रियंका के पार्टी में आने का असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा।
विपक्ष से जंग के लिए BJP के तरकश में तीर तैयार,
2019 में इनके हाथ में कांग्रेस पर हमले की कमान!

महाराष्ट्रः आतंकी संगठन आईएस से संपर्क रखने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार, चाकू, सिम कार्ड बरामद

मुंबई। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएस से संबंध रखने के आरोप में ठाणे और औरंगाबाद से नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, एटीएस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एक समूह के सदस्य सभी नौ संदिग्ध आतंकवादियों को पिछले दो दिनों में एटीएस के दलों ने पकड़ा। अधिकारी ने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर एटीएस ने कई सप्ताह तक नौ लोगों पर नजर रखी और उनके बारे में संबंधित सूचनाएं जुटाई। जब यह पता चला कि वे सक्रिय हो सकते हैं तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठाणे के मुंब्रा शहर में अमृत नगर, कौसा, मोती बाग और अलमास कॉलोनी इलाकों और औरंगाबाद की कैसर कॉलोनी, राहत कॉलोनी और दमडी महल इलाकों में सोमवार को देर रात और मंगलवार को तड़के छापे मारने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान एटीएस के अधिकारियों ने समूह से कुछ रसायन, तेजाब की बोतलें, धारदार चाकू, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और कुछ सिम कार्ड बरामद किए। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक षडयंत्र) और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून और बॉम्बे पुलिस कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरएसएस ऑफिस में बनाते थे खाना, धोते थे बर्तन और साफ करते थे दफ्तर : मोदी ने याद किए पुराने दिन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मशहूर फेसबुक पेज के साथ बातचीत के दौरान अपने बचपन के दिनों को याद किया। उन्होंने हिमालय (Himalaya) में बिताए अपने दो सालों के बारे में भी बातचीत की। फेसबुक पेज पर पीएम मोदी के शब्दों में उनकी कहानी बयां की। पीएम मोदी ने बताया कि उनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ रुझान कैसे हुआ। उनकी कहानी कई हिस्सों में फेसबुक पेज पर शेयर की गई है। मंगलवार को शेयर किए गए हिस्से में उन्होंने हिमालय से वापस लौटने के बाद की जिंदगी के बारे में बात की।

फेसबुक पोस्ट में कहा, हिमालय से वापस आने के बाद मैंने जाना कि मेरी जिंदगी दूसरों की सेवा के लिए है। लौटने के कुछ समय बाद ही मैं अहमदाबाद चला गया। मेरी जिंदगी अलग तरह की थी, मैं पहली बार किसी बड़े शहर में रह रहा था। वहां मैं मेरे अंकल की कैंटीन में कभी-कभी उनकी मदद करता था। आखिरकार मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का फुल टाइम प्रचारक बन गया। वहां पर मुझे जिंदगी के अलग-अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से संपर्क में आने का मौका मिला और वहां मैंने काफी काम भी किया। आरएसएस ऑफिस को साफ करने, साथियों के लिए चाय-खाना बनाने और बर्तन धोने की सबकी बारी आती थी।

पीएम मोदी ने कहा कि वह हिमालय में मिली शांति को नहीं भूलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जिंदगी में संतुलन बनाने के लिए हर साल से पांच दिन निकलाकर अकेले में बिताने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, ज्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं दिवाली के मौके पर पांच दिन ऐसे जगह जाता हूं। ये जगह कहीं भी जंगल में हो सकती है, जहां साफ पानी हो और लोग न हों। मैं उन पांच दिनों का खाना पैक कर लेता हूं। वहां उस दौरान रेडियो, टीवी, इंटरनेट और न्यूजपेपर नहीं होता। उन्होंने कहा कि एकांत उन्हें जिंदगी जीने के लिए मजबूती देता है।

इन बैंकों से लिया ऋण माफी नहीं होगा, हजारों किसान हुए चिंतित

होशंगाबाद। आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक के खाताधारक किसानों को ऋण माफी योजना से दूर रखा जा रहा है। मंगलवार को इन दोनों बैंकों के खाताधार किसानों ने कलेक्ट्रेट में हंगामा कर दिया। ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर माखननगर के ग्राम सांगाखेड़ा, बीकोर, ढोंढई, मजलपुर आदि गांवों के किसान जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो आवेदन देखते ही कलेक्टर आशीष सक्सेना ने यह कह दिया कि इन दोनों बैंकों को सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत नहीं लिया है। इतना सुनते ही किसान आक्रोशित हो गए और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने ही बैठ गए। करीब आधे घंटे तक किसान वहां बैठे रहे। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी भी की और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। किसानों का कहना था कि सभी बैंकों को जब ऋण माफी योजना के दायरे में रखा गया है तो फिर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के खाताधारक किसानों को क्यों नजर अंदाज किया जा रहा है।

किसानों के अचानक धरना प्रदर्शन होने की खबर लगने के बाद प्रशासनिक हल्के में हलचल मच गई थी। किसानों के कलेक्ट्रेट के बाहर जमा होते ही टीएल बैठक को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना था कि लंच टाइम होने के कारण यह बैठक को कुछ देर के लिए रोका गया। दोपहर बाद फिर से बैठक हुई।

होटल की 16वीं मंजिल से खिड़की पर्यटक पर गिरी

बीजिंग। एक होटल की 16वीं मंजिल से खिड़की गिर गई। वह नीचे टहल रही 24 वर्षीय महिला पर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला हॉन्ग कॉन्ग के फाइव स्टार होटल द मीरा का है। घटना में महिला टूरिस्ट के दोस्त को भी मामूली चोट आई हैं। हादसा शिम शा सुई शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बताया जा रहा है कि द मीरा होटल में एक महिला सफाईकर्मी खिड़की की सफाई कर रहा था, तभी खिड़की नीचे से गुजर रही महिला पर्यटक पर गिर गई। हादसे में बुरी तरह घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में महिला सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और फरवरी के अंत तक इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी।

पुलिस अधिकारी चान का यिंग ने कहा है कि खास चाबी से ही होटल का स्टाफ खिड़की खोला जा सकता है। पुलिस का मानना है कि सफाईकर्मी ने खिड़की को खोला और यह तुरंत ही नीचे गिर गई। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है कि किस वजह से होटल की खिड़की गिरी।

सबरीमाला में प्रवेश करने वाली पहली महिला कनक दुर्गा हुई बेसहारा, वन स्टॉप सेंटर में रहने को मजबूर

पेरिन्तलमन्ना। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली 39 साल की महिला कनक दुर्गा अपने घर अस्पताल से वापस लौटीं तो उन्हें अपने घर पर ताला लगा मिला। कनक दुर्गा को मंदिर में प्रवेश करने के चलते ससुराल वालों ने बाहर कर दिया था। इस बीच उनकी सास पर उनसे मारपीट के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा था। अब वो अस्पताल से वापस अपने घर लौटीं तो उन्हें ताला लगा मिला। इसलिए उन्हें फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 44 वर्षीय कनकदुर्गा ने यहां अदालत में घरेलू हिंसा कानून के तहत एक याचिका भी दायर की है और कहा है कि उन्हें अपने पति के घर में रहने का अधिकार है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कनकदुर्गा कोझिकोड चिकित्सकीय महाविद्यालय में उपचार के बाद छुट्टी होने पर अपने पति के घर गई थीं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें घर के बाहर ताला लगा मिला। सदियों पुरानी परंपरा तोड़कर मंदिर में प्रवेश करने को लेकर कनकदुर्गा की सास ने उन्हें कथित रूप से पीटा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस ने बताया कि कनकदुर्गा के पति और उनके संबंधी किराए के एक घर में रहने चले गए हैं। कनकदुर्गा ने यहां वन स्टॉप सेंटर में शरण ली है। उल्लेखनीय है कि अयप्पा मंदिर में रजस्वला आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में हटा दिया था।

इसके बाद नागरिक आपूर्ति विभाग की कर्मी कनकदुर्गा और एक कॉलेज लेक्चरर बिंदु ने दो जनवरी को मंदिर में प्रवेश किया था। वे मंदिर में प्रवेश करने वाली रजस्वला आयु वर्ग की पहली महिलाएं हैं। पेरिन्तलमन्ना सर्किल इंस्पेक्टर टी एस बीनू ने बताया कि कनकदुर्गा को शीर्ष अदालत के आदेशानुसार चौबीस घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम 10 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और वन स्टॉप सेंटर के बाहर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए वन स्टॉप सेंटर का मकसद व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराना है।

60 लाख में बिक रहा दुर्घटनाग्रस्त हुई प्रिंस फिलिप की लैंड रोवर कार का मलबा

लंदन। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप की दुर्घटनाग्रस्त कार लैंड रोवर फ्रीलैंडर का मलबा बिक रहा है। ऑनलाइन बेचे जा रहे इस मलबे की कीमत 65 हजार पाउंड (करीब 59 लाख 58 हजार रुपए) रखी गई है। फिलिप की दुर्घटनाग्रस्त कार के मलबे को बेचने से प्राप्त राशि कैंसर रिसर्च सेंटर यूके को दी जाएगी, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। कार के क्षतिग्रस्त पुर्जे खरीदने के लिए 139 नीलामी की बोलियां लगाई जाएंगी। बताते चलें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 97 वर्षीय पति प्रिंस फिलिप बीते गुरुवार को कार हादसे का शिकार हो गए थे। सैंडीग्राम एस्टेट में प्रिंस फिलिप सड़क हादसे का शिकार हो गए थे।

सूरत ट्राफिक पुलिस कर्मचारियों की ड्युटी में दो घंटे का इजाफा

सूरत। सूरत शहर में बढती ट्राफिक समस्याओं से आम जनता का निजात दिलाने के लिए पुलिस मेहकके कर्मचारियों की दो घंटे की ड्युटी एक्सट्रा कर दी गई है। पो. कमि. सतीष शर्मा ने पुलिस इंस्पेकटर सहित तमाम अधिकारियों के लिए सप्ताह में एक झुट्टी की घोषणा की थी। ट्राफिक ब्रानच के डीसीपी सुधीर कुमार देसाई ने ट्राफिक ब्रानच में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्युटी में दो घंटे बढा कर 10 घंटे करने का आदेश जारी किया है। डीसीपी ट्राफिक ने जारी आदेश में कहा गया है कि वर्किंग डे के दरमियान सुबह 8 बजे से 13 और सांजे 17 से 22 घंटे और जाहेर रजा में सुबह 9 से 13 बजे और शाम 17 से 23 बजे तक काम करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें सर्कल इंचार्ज और रीजीयन इंचार्ज का काम हर रोज कम से कम 25 प्रशेंट पोईन्टों चेक करने का आदेश जारी किया गया है। ड्युटी टाइम में दो घंटे का इजाफा सुनकर ट्राफिक पुलिस में गहमा गहमी शुरु हो गई है।

वराछा रेल्वे कालोनी के क्वार्टस में चोरी

सूरत। वराछा खांड बाजार गरनाला के पास रेल्वे कालोनी के घर नं. 191/सी में से रु. 42500 की चारी हुई। पुलिस द्वारा इस मामले के केश दाखिल कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है। सूरत शहर के वराछा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंदनकुमार विभुति प्रसाद शाह के घर से कुल 42500 रु किमत के सोने के उपर चोर अपना हाथ साफ कर गए।

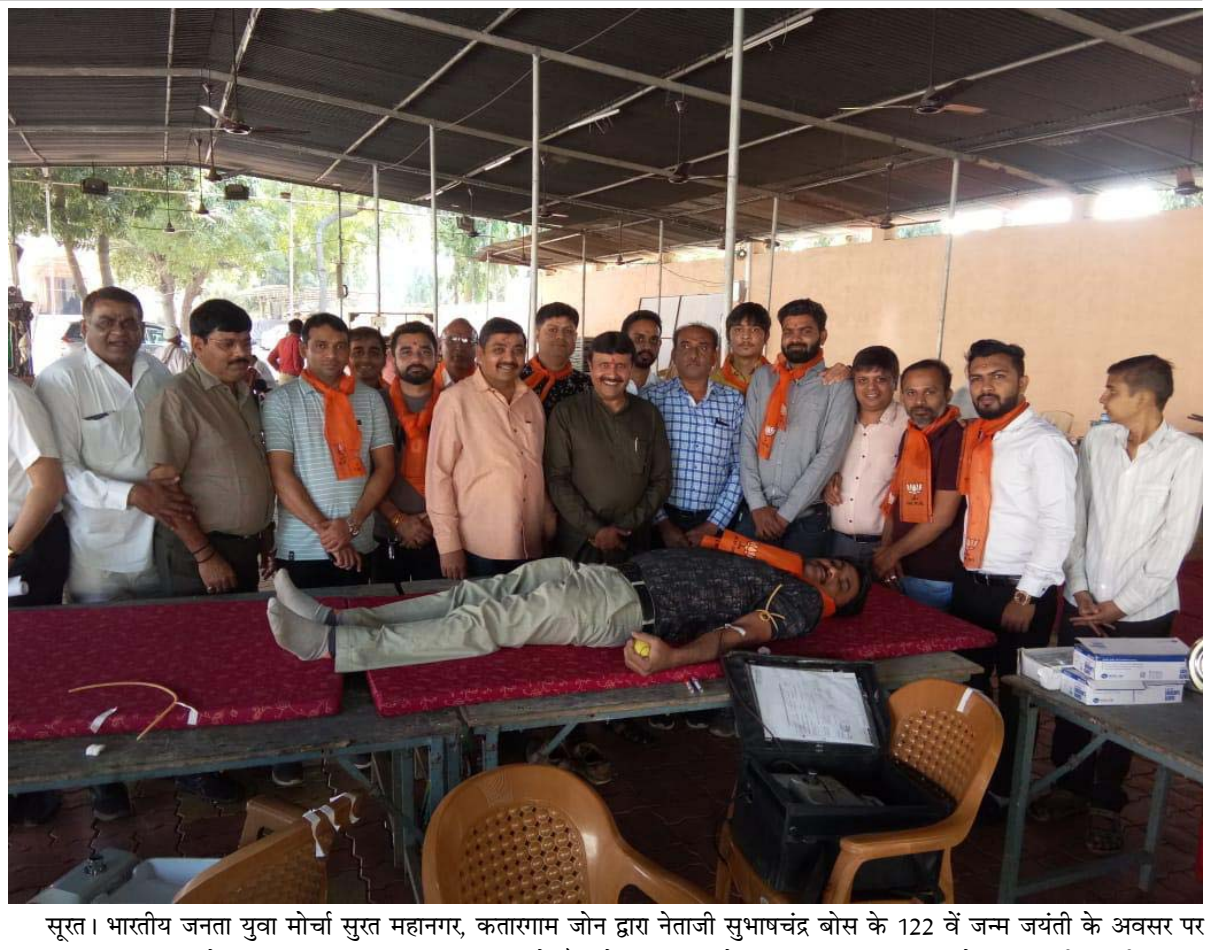

सूरत। भारतीय जनता युवा मोर्चा सुरत महानगर, कतारगाम जोन द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस के 122 वें जन्म जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों शहर वासियों द्वारा रक्तदान किया गया, ये रक्तदान श्री स्वामीनारायण मंदिर, डभोली चार रास्ता, कतारगाम वेड रोड़ सूरत में रखा गया था।

सरकार ने लगाया पबजी गेम पर प्रतिबंध

सूरत। गुजरात सरकार ने प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि बच्चों ने पनप रही पबजी गेम खेलने की आदत को जल्द से जल्द छुटाया जाए। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गुजरात राज्य आयोग की सिफारिशं के बाद राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने सर्क्युलर जारी किया है। मौजूदा दौर में युवक, टीनेजर्स एवं छोटी आयु के बच्चों पर पबजी गैम का विपरीत असर रहो है। गैम खेलने वाले इसमें इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें समय और आसपास की दुनिया का ज्ञान नहीं रहता। गैम

की एक बार लत लग जाने के बाद इससे बाहर निकला काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार ने पबजी गेम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला करते हुए सर्कुलर जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आदेश दिया है कि वह पबजी गेम से होनेवाले नुकसान के बारे में बच्चों को जानकारी दें। गौरतलब है मोबाइल पर पबजी गेम खेला जाता है। इसके चलते बच्चे पढ़ाई से भटक रहे हैं। गेम की विपरीत असरों को देखते हुए गुजरात सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम पर गेम पर बैन लगा दिया गया था।

किंजल की रीट पर आज फैसला होने की संभावना

अहमदाबाद। लोकप्रिय गायिका किंजल दवे की रिट याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पुर्ण हो चुकी है। कोमर्शियल कोर्ट में गीत गाने के खिलाफ पहले जारी किये स्टे को एक दिन के लिए बढ़ा देने से किंजल दवे ने हाईकोर्ट में अर्जी की थी। इस मामले में सुनवाई अब पुर्ण हो चुकी है। मामले में कल गुरुवार के दिन फैसला आने की संभावना दिख रही है। किंजल दवे को कोमर्शियल कोर्ट ने कोपीराईट केस के उल्लंघन के मामले में चार चार बंगडी वाला गीत न गाने का आदेश जारी किया था। कोपीराईट के इस केस में कोमर्शियल कोर्ट ने कल मंगलवार के दिन ओर एक दिन के लिए स्टे लगाया था। कोमर्शियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में किंजल ने याचिका दायर की थी जिसमें आज दोनों पक्षो की ओर से दलीले दी गई। इसके अलावा इस मामले में सुनवाई भी पुरी हो चुकी है। आज हाईकोर्ट में फैसला रिजर्व रखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक कल गुरुवार के दिन फैसला आने की संभावना है। किंजल दवे की ओर से हाईकोर्ट में की गई याचिका में एडवोकेट हर्षित तोलिया और जयदीप वाघेला ने दलीलबाजी की और कहा कि इस केस में कोमर्शियल कोर्ट ने एक्स पार्टी आदेश किया है। अर्जदारों की ओर से की गई दलीले नहीं सुनी गई है। जो कुदरती न्याय के सिद्धांक के खिलाफ है। इन संजोगो में हाईकोर्ट को नीचली कोर्ट के आदेश को गैरकानूनी घोषित करते हुए उसे अस्वीकार करना चाहिए।

भावनगर-बांद्रा टर्मिनस के बीच दौड़ेगी स्पेश ट्रेन

भावनगर। पश्चिम रेलवे भावनगर टर्मिनस से बांद्रा टर्मिनस के बीच २६ ज नवरी को होली डे स्पेशल ट्रेन (०९०४२/०९०४) चलाई जाएगी। यह ट्रेन भावनगर, बोटाद, विरमगाम, अहमदाबाद, नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, बोरीवली एवं बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर ठहरेगी। ट्रेन संख्या ०९०४२ भावनगर से शनिवार ४.१० बजे चलेगी एवं यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह ६.१५

बजे पहुंचेगी। जबकि ट्रेन संख्या ०९०४१ बाद्रा टर्मिनस से शनिवार सुबह ०.२० बजे चलेगी। एवं यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस पर शनिवार दोपहर २.०५ बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में २२ कोच होंगे, जिसमें १ सेकंड एसी कोच, ५ थ्री एसी कोच, १० स्लीपर कोच, ३ जनरल कोच, २ एसएलआर एवं पेन्ट्रीकार होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश किया

नरोडा पाटीया केस में चार दोषितो को जमानत मिली

आरोपियो को अपराधि घोषित करने को लेकर शंका

अहमदाबाद। सुप्रिम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए साल २००२ के नरोडा पाटीया सांप्रदायिक हिंसा के केस में चार अपराधियों की जमानत पर छोड़ने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने का आखिरकार आदेश जारी किया है। सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपराधियों की सजा संदेहात्मक दिख रही है। उल्लेखनिय है कि अहमदाबाद के नरोडा पाटीया इलाके में गोधराकांड के बाद राज्य में फैली हिंसा के दौरान हिंसा हुई थी। जिसमें ९७ लोगों की हत्या कर दी गई थी। उमेशभाई सुराभाई भरवाड, राज कुमार, हर्षद उर्फ मुवडा परमार और प्रकाशभाई राठोड को आखिरकार जमानत मिल गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने इन चारो अपराधियों को १०-१० साल की सजा की थी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपराधियो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। यह अज ी की सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चार अपराधियो को जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारीत की गई सामान्य शर्तो के आधिन जमानत दी है। नरोडा पाटीया केस में गुज रात हाईकोर्ट ने पिछले साल बजरंग दल के नेता बाबु बजरंगी को दोषित घोषित किया था। किन्तु बीजेपी के पूर्व मंत्री माया कोडनानी को सबूतो के अभाव में निर्दोष घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया था कि बज रंग दल के नेता बाबु बजरंगी और अन्यो की याचिकाए भी स्वीकार कर ली गई है। सुनवाई के दौरान नरोडा पाटीया हिंसाग्रस्तो के लिए आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस तरह की मांग करने वाली याचिका अस्वीकार की जा चुकी है। गुज रात हाईकोर्ट ने ३२ आरोपियों में से माया कोडनानी समैत १७ लोगों को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। दुसरी ओर १२ आरोपियों की सजा कायम रखी गई है। दो आरोपियों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। न्यायमूर्ति ए.एम. खानवीलकर के नेतृत्व में बेंच ने आरोपियों के अपराधि घोषित करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को विवादास्पद बताते हुए उन्हे जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी किया था।

राज्य मंत्रिमंडल की मिटींग के फैसला हुआ

आठ लाख से कम आय के युवाओं को अनामत मिलेगा

राज्य सरकार की भर्ती और सरकार मान्य सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए १० फिसदी बैठक अनामत

अहमदाबाद। गुजरात के उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने आज बताया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार ने १० फिसदी आर्थिक अनामत देने का कानून बनाया है। यह कानून के अंतर्गत गुजरात सरकार ने भी पुरे देश में पहली बार इस कानून को लागु करने का फैसला करते हुए आठ लाख से कम आय वाले सामान्य समाज के आर्थिक रुप से कमजोर युवाओं को १० फिसदी आर्थिक अनामत का लाभ देने का निर्णय किया है। आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के नेतृत्व में राज्य मंत्री मंडल की बैठक हुई। इस मिटींग में हुए महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से पुरे देश में सामाजिक समरसता के लिए आर्थिक अनामत देने का निर्णय लिया गया है। आर्थिक अनामत देने के लिए जो मापदंड नक्की किये गए हैं उन्हीं मापदंडो के आधार पर गुजरात में भी आर्थिक रुप से कमजोर युवाओं को मददरुप होने के लिए मंत्रीमंडल के सदस्य के सहित उच्च अधिकारीयों के साथ विचारा विमर्श हुआ। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया है कि गुजरात में साल ७८ से पहले से रहने वाले जनरल कैटेगरी के समाज के सभी लोगों को यह लाभ मिलेगा। गुजरात सरकार की नीति के तहत प्रत्येक भर्ती में ३३ फिसदी बैठके महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाती है। उसी के अनुसार जनरल समाज की अनामत बैठको में भी ३३ फिसदी बैठके महिलाओं के लिए अनामत होगी। राज्य सरकार की नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आय का यह एक ही नियम लागु होगा। भारत सरकार की नौकरी और शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए नियम केन्द्र सरकार के द्वारा नक्की हुए लागू होंगे। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भी अब से १० फिसदी आर्थिक अनामत की व्यवस्था के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाएगी। नीतिन पटेल ने बताया है कि केन्द्र सरकार की ओर से १० फीसदी आर्थिक अनामत देने के लिए आठ लाख की आय के साथ जमीन मालिकी और आवास घर की मालिकी या खुले प्लोट की मालिकी के साथ अलग अलग व्यवस्था को ध्यान में लिया जाएगा। गुजरात सरकार ने और अधिक राहत देते हुए मात्र आय का एक ही मापदंड रखने का फैसला किया है। आठ लाख से कम आय वाले समाज के परिवार के युवानो को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आर्थिक अनामत का लाभ मिलेगा। कुछ ही दिनो में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होगी। पटेल ने कहा कि वार्षिक आठ लाख की आय में उम्मिदवार खुद, अपने माता-पिता और १८ साल से कम आयु के भाई बहनो की आय भी गिनी जाएगी। यह आय में कोई भी नौकरी के वेतन, खेतीवाडी की आय, धंधा व्यवसाय की आय भी गिनी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में साल १९८८ से पहले से रहने वाले परिवारो की वार्षिक आय आठ लाख से कम होने पर उन्हें अनामत का लाभ मिलेगा।

अहमदाबाद में १२ प्रोजेक्ट

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की ओर से वाइब्रेंट गुज रात सम्मेलन के तहत विभिन्न कंपनियों की ओर से किए गए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। जारी की गई २७ प्रोजेक्ट की सूची में सर्वाधिक १२ प्रोज क्ट अहमदाबाद और इसके आस-पास के हैं। इन प्रोज क्ट के इस वत्तीय वर्ष के अंत तक कुछ प्रोजेक्ट के उद्घाटन, शिलान्यास या आरंभ होने की बात कही गई है।

कंपनी का नाम	प्रोजेक्ट विवरण	प्रोजेक्ट स्थल
महिन्द्रा	इंडस्ट्रियल पार्क	सुरेन्द्रनगर
पावरिका लि.	१०० मेगावोट पवन ऊर्जा संयंत्र	जामनगर
टोरेन्ट पावर	घोलेरा एसआईआर में ऊर्जा सुविधा	अहमदाबाद
बोल्टबेकहोमे	एफएमसीजी निर्माण	अहमदाबाद
मुंद्रा सोलर (अदाणी)	१२०० मेगावोट सोलर सेल प्लान्ट ८०० मेगावोट का कार्य जारी	भुज
मुराकामी	रियर व्यू मिरर निर्माण	अहमदाबाद
अदाणी पोर्ट एंड एसईजेड	कंटेनर टर्मिनस ५	मुंद्रा
शापुरजी पलूनजी	छारा में एलपीजी टर्मिनस	जूनागढ़
ऑटोमोटिव इलेक्ट्रोनिक्स	लिथियम आयरन बैटरी पैक	अहमदाबाद
क्रोमेनी स्टील्स	स्टेनलेस स्टील प्लांट	कच्छ
जेसीबी इंडिया	स्टील कंपोनेट, फैब्रिकेशन निर्माण	पंचमहाल
मूबिया ऑटोमेटिव	कॉइल स्प्रिंग निर्माण	अहमदाबाद
नानलियू मैन्यूफैकचरिंग	टेक्निकल टेक्सटाइल	अहमदाबाद
मैरिको लि.	पर्सनल केयर उत्पाद उत्पादन	अहमदाबाद
पिन्गाओ ग्रुप पावर		
एमजी मोटर्स (शंघाई ऑटोमोटिव) पैसेन्जर		पंचमहाल
दीपक फेनोलिक्स	पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन	दहेज
बालाजी वेफर्स	एग्रो प्रोसेसिंग निर्माण	राजकोट
मुंद्रो सोलर	पवन-सौर ऊर्जा के लिए प्रोजेक्ट	भुज
शिंगसेन	स्पेशल स्टील निर्माण	धोलेरा
एमआरएफ	टायर निर्माण	दहेज
सुजुकी इंडिया	कार निर्माण दुसरी लाइन का उद्घाटन	अहमदाबाद
वेलस्पन ग्रुप	इंडस्ट्रीयल पार्क, टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोजेक्ट का विस्तार	कच्छ
जीएससीएल व नाल्को	अल्युमिनियम निर्माण	दहेज
टेकनोट्रेड्स ऑटोपार्क	जापानी इंडस्ट्रीज के लिए प्लग एंड प्ले	अहमदाबाद
अरविंद लि.	बावला में गारमेन्ट युनिट	अहमदाबाद
चिड़ीपाल ग्रुप	टेक्सटाईल निर्माण	खेड़ा

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)